

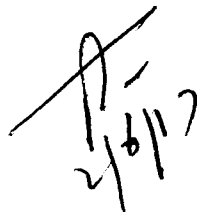
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु लगभग 4000 कि०मी० की लम्बाई में ग्रामीण पथों का निर्माण कराने हेतु New Development Bank (BRICS) से ₹ 2310 करोड़ (US\$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB(BRICS) के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण करने लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के 27 Non-IAP जिलों, यथा, अररिया, किशनगंज, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना राज्य सरकार का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में लगभग 38000 कि०मी० पथों का निर्माण/उन्नयन किया जाना है। 38000 कि०मी० पथ के निर्माण पर वर्तमान दर के अनुसार लगभग ₹30000 करोड़ की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की अपनी निधि से अबतक ₹5492 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इस राशि से 10191 कि० मी० पथ का निर्माण राज्य योजना से किया जा रहा है।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका-2-2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं बाह्य श्रोत से करने का प्रावधान है।



3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 66/2015-607/वि0 दिनांक 09.07.2015 के द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्रके आलोक में NDB(BRICS), बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु 10000 कि० मी० पथों के निर्माण हेतु कुल ₹8000 (US\$ 1333.00 million) करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध NDB(BRICS) बैंक से ₹ 5600 करोड़ एवं राज्य की अपनी निधि से ₹2400 करोड़ का प्रस्ताव मांगा गया था। वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक WM-66/2015/F-692 दिनांक 04.08.2015 के द्वारा प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। दिनांक-02.09.2015 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संपन्न 52वीं संवीक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में ₹8000 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 10000 कि० मी० पथों (राशि ₹8000 करोड़) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा।
4. तदनुसार वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा Debt Sustainability तथा 30% Counterpart Funding की सहमति प्रदान की गयी।
5. इस योजना का कार्यान्वयन NDB(BRICS) बैंक की मार्गदर्शिका के साथ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्तावित निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Rural Road Project II) के लिए निर्धारित Model Bidding Document(MBD) के अनुसार होगी।
6. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु NDB(BRICS) बैंक के Mission Team के दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 तक बिहार भ्रमण के दौरान प्रथम चरण में ₹3300 करोड़ (500 million US\$) की लागत के विरुद्ध लगभग 4000 कि०मी० ग्रामीण पथों को NDB(BRICS) बैंक से प्राप्त सहायता से निर्माण कराने हेतु सहमति बनी है। इसमें से DEA, भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात् US\$ 350 million (₹2310 Crore)



NDB(BRICS) बैंक ऋण अंश एवं 30 % अर्थात US\$ 150 million (₹990 Crore) राज्यांश होगा।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

किशनगंज को छोड़कर शेष 26 Non-IAP जिलों में लगभग 4000 कि०मी० की लंबाई में NDB(BRICS) के मापदंडों के अनुरूप चयनित ग्रामीण पथों का निर्माण कराने के लिए New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US\$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB (BRICS) के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :- 02.06.17
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

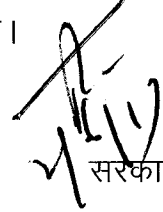
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक:- 02.06.17
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राज्यकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव

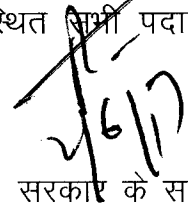
ज्ञापांक :- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 /पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

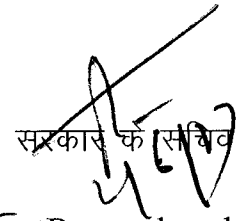
ज्ञापांक :- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :- 02.06.17

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

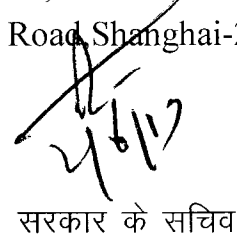
ज्ञापांक :- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :- 02.06.17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

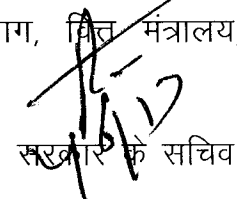
Memo :- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /Patna dated:- 02.06.17

Copy to:- Shri Garvit Sah, Project Team Leader, Bihar Rural Roads Project, New Development Bank, 333 Lujiazui Ring Road Shanghai-200120 for kind information and necessary needful action.


सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :- 02.06.17

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (MI), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव